

भारत का सहकारिता आंदोलन

प्रलम्बिस के लयि:

NABARD, भारत सरकार अधनियम 1919, बहु-राज्य सहकारी समिति, राज्य की नीति के नरिदेशक ततत्व, शहरी सहकारी बैंक

मेन्स के लयि:

समावेशी वकिस के लयि सहकारी समितियिँ, सहकारी समितियिँ को मज़बूत करने हेतु सरकार के प्रयास, सहकारी आंदोलन का ऐतहिसकि वकिस।

[सरोत: पी.आई.बी](#)

चर्चा में क्योँ?

भारत नवंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है, जिसका आयोजन भारतीय कृषि उर्वरक सहकारी (IFFCO) द्वारा 18 ICA सदस्य संगठनों के सहयोग से किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देना है, जिसमें 29 क्षेत्रों की 800,000 से अधिक समितियाँ शामिल हैं।



सहकारी समितियाँ क्या हैं?

- परचिय:
 - सहकारी समिति एक स्वैच्छिक सदस्य-स्वामित्व वाला संगठन है जसै सामान्य आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लयि बनाया गया है।
 - सहकारी समितियिँ स्व-सहायता, पारस्परिक सहायता एवं सामुदायिक कल्याण पर बल देती हैं।
- सहकारी आंदोलन का ऐतहिसकि वकिस:
 - स्वतंत्रता-पूर्व चरण: इस दौरान सहकारी सिद्धांत स्थानीय पहलों के माध्यम से अनौपचारिक रूप से अस्तित्व में थे जैसे कि चिटि फंड, मद्रास में मयुचुअल-लोन एसोसिएशन और गाँव के तालाबों या जंगलों (जसै देवराई या वनराई के रूप में जाना जाता है) जैसे संसाधनों का

सामुदायिक प्रबंधन। हालाँकि इसके लिये औपचारिक कानून 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बना।

- मद्रास **प्रेसीडेंसी** में वित्तीय सहायता देने के लिये **पारस्परिक ऋण संघों** (जन्हें 'नधि' के नाम से जाना जाता था) का गठन किया गया।
- **पंजाब** में सभी सह-हसिसेदारों के लाभ के लिये गाँव की भूमि की देखरेख के लिये वर्ष 1891 में एक सहकारी समिति बनाई गई थी।
- वर्ष 1904 में **सहकारी ऋण समिति अधिनियम** द्वारा भारत में सहकारी समितियों को कानूनी मान्यता मिलने के साथ उनके गठन, सदस्यता, लाभ और वधितन संबंधी दिशा-निर्देश निर्धारित किये गए। हालाँकि इसके तहत गैर-ऋण एवं अन्य समितियों को शामिल नहीं किया गया।
- **भारत सरकार अधिनियम, 1919** द्वारा प्रांतों को सहकारी समितियों पर वधि बनाने का अधिकार दिया गया जिसके परिणामस्वरूप **बॉम्बे सहकारी समिति अधिनियम, 1925** (जो पहला प्रांतीय सहकारी कानून था) पारित हुआ।
- **सहकारी समिति अधिनियम, 1912** के तहत वपिणन, हथकरघा और कारीगर समितियों को भी शामिल किया गया।
- वर्ष 1914 में **मैक्लेगन समिति** ने केंद्र, प्रांत और ज़िला स्तर पर त्रस्तरीय सहकारी बैंकिंग प्रणाली का प्रस्ताव रखा।
- वर्ष 1942 में भारत ने बहु-राज्यीय सहकारी समितियों को वनियमि कर देने के लिये **बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम** पारित किया तथा इसकी व्यावहारिकता के लिये केंद्र के रजिस्ट्रार की शक्तियाँ राज्य रजिस्ट्रार को सौंप दी गईं।
- **स्वतंत्रता के बाद का चरण:** स्वतंत्रता के बाद भारत में आर्थिक शक्ति का वकेंद्रीकरण करने तथा सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक विकास में लोक भागीदारी को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया। **पहली पंचवर्षीय योजनाओं** से शुरू होकर, ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय तक, सहकारी समितियाँ **पंचवर्षीय योजनाओं** में प्रमुख बन गईं।
- वर्ष 1963 में **राष्ट्रीय सहकारी विकास नगिम (NCDC)** और वर्ष 1982 में स्थापित **NABARD**, ग्रामीण ऋण के साथ सहकारी विकास को समर्थन देने के क्रम में निर्णायक सदिध हुए।
- वर्ष 1984 में भारत ने सहकारी वधियों को एकीकृत करने के क्रम में **बहु-राज्य सहकारी संगठन अधिनियम पारित किया**, जिसे वधिक सामंजस्य हेतु वर्ष 2002 की **राष्ट्रीय सहकारी नीति** द्वारा और अधिक समेकित किया गया।
 - **बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम 2023** का उद्देश्य बहु-राज्य सहकारी समितियों में पारदर्शिता और संरचनात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देना है, जिससे सहकारी समितियों को अधिक स्वतंत्रता मिल सके।
- **97वें संवधान संशोधन अधिनियम 2011** द्वारा सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार को **मूल अधिकार (अनुच्छेद 19)** के रूप में स्थापित किया गया।
 - सहकारी समितियों के संदर्भ में **राज्य की नीति के निर्देशक सदिधांत (अनुच्छेद 43-B)** में प्रावधान किया गया।
 - संवधान में एक नया **भाग IX-B** शामिल किया गया जिसका शीर्षक था **"सहकारी समितियाँ"** (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT)।
 - **बहु-राज्य सहकारी समितियों (MSCS)** को नयितरति करने संबंधी वधि निर्माण हेतु संसद को अधिकार दिया गया तथा अन्य सहकारी समितियों के लिये राज्य वधिनसभाओं को प्राधिकार सौंपे गए।
- वर्ष 2021 में गठित **सहकारिता मंत्रालय** द्वारा आर्थिक प्रगति के प्रमुख चालक के रूप में सहकारी समितियों को समर्थन देने के क्रम में सरकार की प्रतबिद्धता को और मज़बूत किया।

भारत में सहकारी समितियों के प्रकार क्या हैं?

- **उपभोक्ता सहकारी समितियाँ:** बचौलियों को हटाकर उत्पादकों से सीधे स्रोत प्राप्त करके उचित मूल्य पर सामान उपलब्ध कराती हैं। उदाहरणार्थ, **केंद्रीय भंडार**।
- **उत्पादक सहकारी समितियाँ:** कच्चे माल और उपकरण सहित आवश्यक उत्पादन सामग्री की आपूर्ति करके छोटे उत्पादकों की सहायता करती हैं।
- **सहकारी वपिणन समितियाँ:** छोटे उत्पादकों को उनके उत्पाद सामूहिक रूप से बेचने में सहायता करना, उदाहरणार्थ, **आनंद मलिक यूनिन लमिटिड (अमूल)**।
- **सहकारी ऋण समितियाँ:** बचत और ऋण जैसी वित्तीय सेवाएँ प्रदान करती हैं, जैसे, **शहरी सहकारी बैंक, ग्राम सेवा सहकारी समिति**।
- **सहकारी कृषि समितियाँ:** छोटे किसानों को बड़े पैमाने पर कृषि का लाभ दिलाने में सहायता करना, जैसे **लफिट सचिाई सहकारी समितियाँ, सहकारी समितियाँ और जल पंचायतें**।
- **आवास सहकारी समिति:** अपने सदस्यों के लिये भूमि अधिग्रहण और विकास करके लागत प्रभावी आवास विकल्प प्रदान करती हैं, उदाहरण के लिये **कर्मचारी आवास समितियाँ और मेट्रोपोलिटन आवास सहकारी समिति**।

भारत में सहकारिता के संबंध में कुछ हालिया विकास और प्रमुख पहल क्या हैं?

- **सहकारिता मंत्रालय की भूमिका:**
 - प्रत्येक गाँव को सहकारी समितियों से जोड़ने के लिये **सहकार से समृद्धि** अभियान शुरू किया गया।
 - **प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS)** के लिये **आदर्श उपनयम**, ताका प्रशासन में सुधार हो और समावेशिता बढ़े।
 - 63,000 PACS को आधुनिक बनाने और **NABARD** के साथ जोड़ने के लिये 2,516 करोड़ रुपए की परियोजना के माध्यम से **PACS का कम्प्यूटरीकरण**।
 - **डेयरी, मत्स्य पालन और अनाज भंडारण** जैसे वभिन्न कार्यों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में नए **बहुउद्देशीय PACS की स्थापना**।
- **सहकारिता को मज़बूत करने के लिये सरकार के प्रयास:**
 - **वकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना:** अपव्यय और परविहन लागत को कम करने के लिये PACS स्तर पर गोदामों और कृषि-बुनयादी ढाँचे की स्थापना।
 - **कृषक उत्पादक संगठनों (FPO) का गठन:** बेहतर बाज़ार संपर्क के साथ किसानों को सशक्त बनाना।
 - **PM भारतीय जन औषधि केंद्र:** जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाएँ उपलब्ध कराने के लिये PACS का उपयोग किया जा रहा।

है।

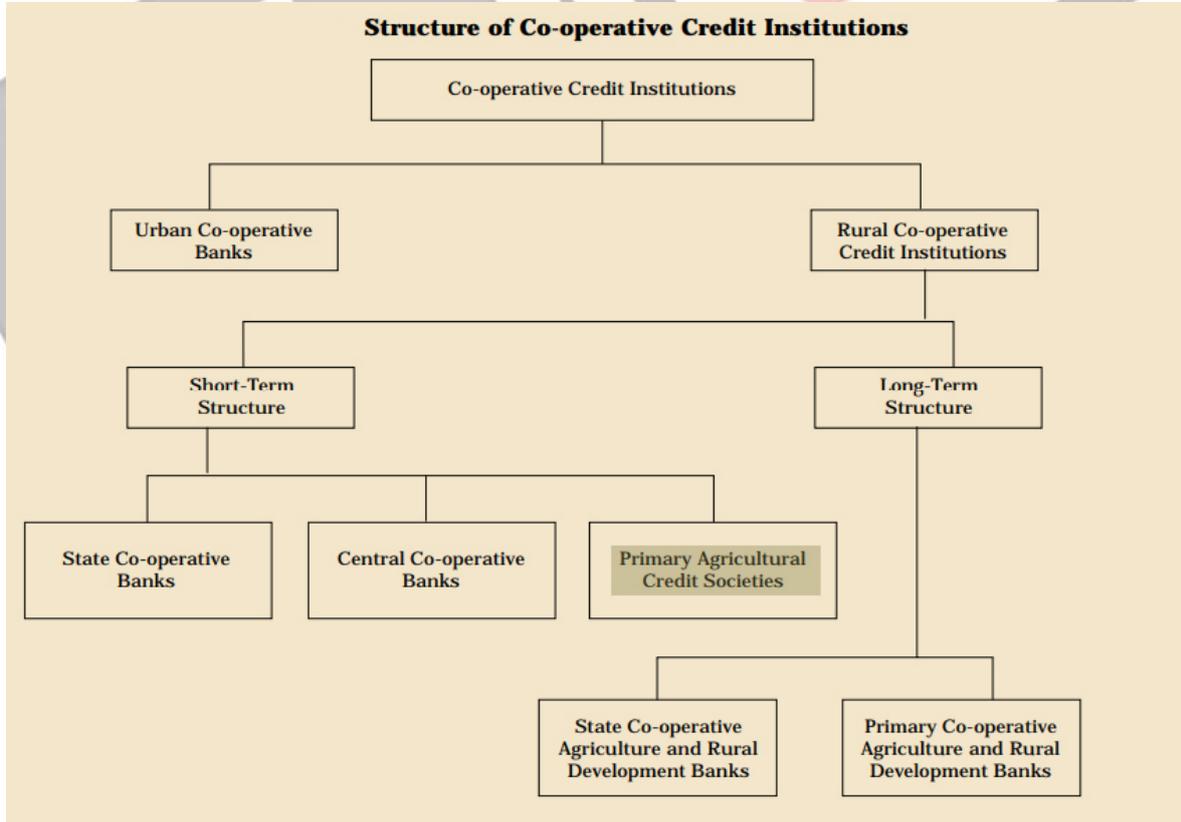
- **PM-कृषुम अभिसरण:** PACS सदस्यों को सचिाई के लिये सौर पंप अपनाने में सक्षम बनाना, सतत् कृषपिदधतयिों को बढ़ावा देना।
- **ग्रामीण वकिस और वत्तिलीय समावेशन पर प्रभाव:**
 - **वत्तिलीय समावेशन के लिये सहकारिताएँ:** शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंक जैसी सहकारी संस्थाएँ कफियाती ःण उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिताी हैं, वशिष रूप से कसिानों और छोटे उदयमयिों को, जो मुखयधारा की बैंकगि सेवाओं से वंचति हैं।
 - **महिलाओं और हाशयि पर पड़े समुदायों का सशक्तकरण:** महिला सहकारी समतियिों और ग्रामीण सहकारी समतियिों आर्थकि अवसर पैदा करने और वंचति क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार लाने पर ध्यान केंदरति करती हैं।

भारत में सहकारिता के उदाहरण

- **HOPCOMS (बागवानी उत्पादकों की सहकारी वपिणन और प्रसंस्करण सोसायटी):** HOPCOMS, कृषउत्पादों के प्रत्यक्ष वपिणन के लिये वर्ष 1965 में स्थापति एक कसिान सोसायटी है। इसका मुख्यालय बंगलूरु में है।
- **लजिजत पापड़ (श्री महिला गृह उदयोग लजिजत पापड़):** पापड़ उत्पादन के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने वाली एक प्रेरक महिला सहकारी संस्था
- **इंडयिन कॉफी हाउस:** यह भारत में एक रेस्तराँ शृंखला है जसिे कई श्रमकि सहकारी समतियिों द्वारा चलाया जाता है। इस शृंखला की शुरुआत कॉफी सेस कमेटी द्वारा की गई थी, जसिका पहला आउटलेट - तब 'इंडयिा कॉफी हाउस' नाम से - 1936 में चर्चगेट, बॉम्बे में खोला गया था। इसे इंडयिन कॉफी बोर्ड द्वारा संचालति कयिा जाता था।

प्राथमकि कृष ःण समतियिाँ

- PACS ग्राम स्तरीय सहकारी ःण समतियिाँ हैं जो राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंकों (SCB) की अधयक्षता में त्रसितरीय सहकारी ःण संरचना में अंतमि कड़ी के रूप में कार्य करती हैं।
- पहला PACS 1904 में गठति कयिा गया था।
- SCB से ःण ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCB) को हस्तांतरति कयिा जाता है, जो ज़िला स्तर पर काम करते हैं। DCCB PACS के साथ काम करते हैं, जो सीधे कसिानों से नपितते हैं।
- PACS कसिानों को वभिन्न कृषसंबंधी गतविधियिों के लिये अलपावधिएवं मध्यमावध कृष ःण उपलब्ध कराती हैं।



प्रश्न: "भारतीय शासकीय तंत्र में गैर-राजकीय कर्त्ताओं की भूमिका सीमिति ही रही है।" इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2016)

प्रश्न: "गाँवों में सहकारी समितियों को छोड़कर ऋण संगठन का कोई भी ढाँचा उपयुक्त नहीं होगा।" - अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण। भारत में कृषि वित्त की पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिये। कृषि वित्त प्रदान करने वाली वित्त संस्थाओं को कनि बाधाओं और कसौटियों का सामना करना पड़ता है? ग्रामीण सेवार्थियों तक बेहतर पहुँच और सेवा के लिये प्रौद्योगिकी का कसि प्रकार उपयोग कया जा सकता है?" (2014)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-s-cooperative-movement>

